RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : बुधवार 17 अगस्त 2022 वर्ष 04 अंक 106 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
# रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

## शिंदे सरकार की अपील

## आज सुबह 11 बजे पूरे महाराष्ट्र की जनता एक साथ गाए राष्ट्रगान...

**मुंबई:** महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने को यादगार बनाने का फैसला कयि है। सरकार ने महाराष्ट्र की जनता से बुधवार सुबह 11 बजे साथ मिलकर राष्ट्रगान के सामूहिक गायन में हिस्सा लेने की अपील की है। सरकार ने कहा कि देश भर में राष्ट्रगान (जन, गण, मन) का सामूहिक गायन सुबह 11 बजे से शुरू होकर 11:01 बजे समाप्त हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के सभी विभागों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सभी लोगों के लिए इसमें



हिस्सा लेना अनिवार्य है, वहीं सभी नागरिकों से भी इस गायन में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

आदेश में कहा गया है कि यह केंद्र सरकार के ह्रस्वराज महोत्सवह्न का हिस्सा है। आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिष्ठान, व्यापारी और अन्य सरकारी विभागों, केन्द्र सरकार के तहत आने वाले सरकारी विभागों से भी इसमें शामिल होने की अपेक्षा की जाती है। छात्रों से आशा की जाती है कि राष्ट्रगान गाने के लिए वे खुले मैदानों में एकत्र होंगे।

**तेलंगाना में एक साथ गाया गया सामूहिक राष्ट्रगान**

उधर, स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह के मौके पर राष्ट्रगान के सामूहिक गायन के लिए पूरा तेलंगाना मंगलवार को कुल 58 सेकेंड के लिए जैसे ठहर सा गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य भर के महत्वपूर्ण स्थानों पर सुबह साढ़े 11 बजे ट्रैफिक रोक दिया गया और जन गण मन का गायन हुआ। गायन सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य जगहों पर हुआ।

## मुंबई पुलिस ने 513 किलो ड्रग्स की जब्त...!

**एक हजार करोड़ रुपये से अधिक है कीमत**

**मुंबई :** मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल की वर्ली यूनिट ने गुजरात के भरूच जिले में एक ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने भरूच के अंकलेश्वर इलाके से लगभग 513 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया है। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1,026 करोड़ रुपये है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें से 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और दो आरोपी एंटी नार्कोटिक्स सेल की कस्टडी में हैं। इससे पहले मुंबई पुलिस ने शिवाजी नगर से जो ड्रग्स की खेप पकड़ी थी उसके बाद से ही पुलिस इसका सोर्स पता लगाने



में जुटी हुई थी। मुंबई पुलिस को इस खेप को पकड़ने में पांच महीने तक मशक्कत करनी पड़ी है। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल इस पर लगातार काम कर रही थी। पुलिस को लगता है कि ये एक बड़ा अंतरराज्यीय ड्रग्स गिरोह है, जो कई राज्यों में फैला हुआ है। ये गिरोह खासतौर पर युवाओं को निशाना बनाता है। ये ड्रग्स हाई प्रोफाइल सर्कल में सप्लाई की जाती है। बता दें कि, इससे पहले बीती 29 मार्च को मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल की वर्ली यूनिट ने मुंबई के शिवाजी नगर इलाके से ड्रग तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनके पास से करीब 4.5 करोड़ रुपये के एमडी (ड्रग्स) का स्टॉक भी जब्त किया था। तभी से पुलिस इस गिरोह की जांच में जुट गई थी। एंटी नार्कोटिक्स सेल इसके बाद बीती 3 अगस्त को पालघर जिले के नालासोपारा (मुंबई के बाहरी इलाके) से 1,403 करोड़ रुपये मूल्य का 701 किलोग्राम मेफेड्रोन (एमडी) जब्त किया था।

## भोजन की खराब गुणवत्ता पर भड़के शिवसेना विधायक, कर्मचारी को जड़ दिए थप्पड़

**मुंबई :** शिवसेना विधायक संतोष बांगर ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में मध्याह्न भोजन बना रहे एक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों को खराब गुणवत्ता का भोजन परोसा जा रहा है। सोमवार को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि बांगर एक रसोई में काम करने वाले कर्मचारी को दो बार थप्पड़ मारते हैं, जहां मध्याह्न भोजन तैयार किया जा रहा था। वह कर्मचारी से भोजन को लेकर सवाल-जवाब करते हुए



नजर आ रहे हैं।

शिवसेना विधायक ने बाद में पत्रकारों से कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के लिए रसोई में तैयार किए जा रहे भोजन में जिस सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था उसकी गुणवत्ता बेहद खराब थी। शिवसेना के, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले धड़े के विधायक बांगर ने दावा किया यह सरकारी निधि की लूट है। वे गरीब लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। राज्य सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

# महाराष्ट्र में शिंदे के विधायक की दादागिरी!

## बोले- 'हाथ-पैर तोड़ दो...जमानत मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना'

**मुंबई :** महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक प्रकाश सुर्वे की दादगिरी सामने आई है। विधायक ने एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे गुट पर निशाना साधते हुए कहा-आने वाले चुनाव में हम उनको उनकी औकात देखा देंगे। इतना ही उन्होंने समर्थकों से कहा कि जो भी आपके काम के बीच में आए तो उसका हाथ तोड़ देना, हाथ नहीं तो टांग तोड़ देना...बाद मैं आपकी जमानत करा लूंगा।

**हम किसी से लड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमसे लड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं**

दरअसल, विधायक प्रकाश सुर्वे दहिसर कोकणी पाड़ा बुद्ध विहार में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए यह भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने ठाकरे गुट पर तंज कसते हुए कहा- अब किसी की



दादागिरी नहीं चलने वाली है। कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। इसके बाद भी कोई आपके काम के बीच में आता है तो उसके हाथ नहीं तोड़ सकते तो टांग तोड़ देना। दूसरे दिन मैं जमानत करा दूंगा। हम किसी से लड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमसे लड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप टेंशन नहीं लेना।

**देश मना रहा अमृत महोत्सव और विधायक दे रहे ऐसे बयान**

विधायक के इस विवादित बयान के बाद शिवसेना नेताओं की तरफ से दहिसर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत शिवसेना के पूर्व पार्षद उदेश पाटेकर ने दर्ज करवाई है। उन्होंने पुलिस को विधायक के विवादित बयान की वीडियो क्लिप सौंपी है। पाटेकर ने अपने शिकायत पत्र में कहा है कि आज जब देश स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मना रहा है तो देश के संविधान और लोकतंत्र के ट्रस्टी माने जाने वाले विधायक ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं। इसलिए इस तरह का भड़काऊ भाषण देने वाले विधायक पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

## संपादकीय / लेख

# मुफ्त का लुत्फ

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

**यह सुखद ही है कि चुनाव के दौरान मुफ्त प्रलोभन को वोट बटोरने की मशीन बनाने की तिकड़मों को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया। अन्यथा देश के राजनेता इस मुद्दे पर खुलकर कहने से बचते रहे हैं। हालांकि, कमोबेश सभी राजनीतिक दल इस रेवड़ी बांटने की दलदल में धंसे हुए हैं। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की उदासीनता निस्संदेह चिंता की बात है जिसको लेकर शीर्ष अदालत कड़ी टिप्पणियां कर चुकी है। यूं तो सुप्रीम कोर्ट कई बार केंद्र सरकार व वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी संस्थाओं को इस मुद्दे पर निर्णायक राय देने को कह चुका है। अब लगता है कि कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद इस दिशा में कोई कारगर पहल हो पाये। कोर्ट साफ कह चुका है कि मुफ्त की संस्कृति के चलते देश की आर्थिकी को बड़ी चोट पहुंचती है। अदालत चुनाव के दौरान मुफ्त बांटने की परिपाटी पर रोक लगाने के लिये केंद्र सरकार को एक समिति बनाने के लिये कह चुकी है जो व्यापक स्तर पर इस मुद्दे पर निष्पक्ष विचार करे। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही है कि देश में व्याप्त आर्थिक विसंगतियों के चलते कमजोर वर्ग को मुफ्त की सेवाएं उपलब्ध कराने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकारें ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं चला भी रही हैं। लेकिन इसके समर्थकों व विरोधियों की बात सुनकर ही निष्पक्ष ढंग से इस मुद्दे पर फैसला किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर विमर्श के बिना यदि सभी कल्याणकारी मुफ्त की योजनाओं को रोका गया तो समाज के निर्धन तबके को खासा नुकसान होगा। ऐसे में इस मुद्दे को तार्किक परिणति देने के लिये जरूरतमंद वर्ग की चिंताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। ताकि मुद्दे की चुनौती से निबटा जा सके और वंचित समाज को नुकसान भी न हो।**

**दरअसल, राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणा पत्र में किये गये लोकलुभावन वायदों पर अंकुश लगाने के लिये बाध्य करने की जरूरत है। इस काम में चुनाव आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विडंबना यह है कि पिछले कुछ दशकों में चुनाव आयोग की लचर भूमिका के चलते राजनीतिक दलों की मनमानी बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट भी आयोग की ढुलमुल कार्यशैली पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। एक समय टीएन शेषन जैसे सख्त मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक विद्रूपताओं पर किसी हद तक अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन उनके उत्तराधिकारी आयोग की इस गरिमा को बनाये नहीं रख सके। निस्संदेह, रेवड़ी बांटने की राजनीति पर चुनाव आयोग बेहतर ढंग से अंकुश लगा सकता था। लेकिन उसकी निष्पक्ष भूमिका को लेकर गाहे-बगाहे सवाल उठते रहे हैं। आखिर राजनीतिक दलों को ऐसी आजादी क्यों दी जाती है कि वे मेहनतकश जनता के कर से अर्जित धनराशि सस्ती लोकप्रियता के लिये वायदे पूरे करने में खर्च करें। यदि वाकई लोकलुभावन नीति की जरूरत राजनीतिक दलों को है तो वे इसके लिये फंड अलग से जुटाएं। फिर वे जो चाहे वायदे करें। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जनकल्याण की योजनाओं के लिये आवंटित धन का दुरुपयोग किया जाता है। फिर केंद्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर घी पीने की कहावत को चरितार्थ किया जाता है। जबकि पहले से ही कर्ज में डूबे राज्यों की माली हालत इन मुफ्त की बिजली, पानी व अन्य मुफ्त के वायदों से और खराब हो जाती है। फलतः इन राज्यों में पैदा होने वाला हर बच्चा भारी-भरकम कर्ज सिर पर लेकर पैदा होता है, लेकिन राज्य की आर्थिकी के लक्ष्यों से जुड़े सरोकारों से राजनीतिक दलों का कोई लेना-देना नहीं होता। जनता को राहत मिलनी चाहिए, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए लेकिन राजनीतिक विलासिता के लिये इसमें कोई जगह न हो।**

editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

# कचरा कैपिटल बनती जा रही है मुंबई, रोज निकल रहा है 6500 मीट्रिक टन कूड़ा!

**मुंबईः** कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान मुंबई में सफाई का स्तर काफी अच्छा हो गया था। लेकिन प्रतिबंधों के उठने के बाद मुंबई में फिर कचरे का उत्पादन बढ़ गया है। मुंबई में अब प्रतिदिन 6500 मीट्रिक टन कचरा पैदा हो रहा है। कोरोना के दौरान यह 3500 से 4000 मीट्रिक टन था। बीएमसी ने 2 अक्टूबर, 2017 से सोसायटियों में कचरा प्रबंधन अनिवार्य किया है। इसके तहत 20 हजार वर्गमीटर से बड़ी सोसायटियों और 100 किलो से ज्यादा कचरा निर्माण करनेवाली सोसायटियों में गीले कचरे के डिस्पोजल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। सोसायटी में कचरे से खाद निर्माण की व्यवस्था करने वाली सोसायटियों को प्रॉपर्टी टैक्स में बीएमसी छूट भी दे रही है। इसके बावजूद मुंबई में कचरे का उत्पादन बढ़ रहा है। मुंबई में 35000 रजिस्टर्ड सोसायटियां हैं, जिनमें से महज 1300 सोसायटियों में कचरे के डिस्पोजल की प्रक्रिया शुरू हुई है। बीएमसी का घनकचरा विभाग प्रतिदिन औसतन 6 हजार मीट्रिक टन से अधिक कचरा उठा कर डंपिंग ग्राउंड में फेंकता है। इस समस्या के समाधान के लिए बीएमसी ने मुंबई में शत प्रतिशत कचरा प्रॉसेस करने का रोडमैप बनाया है। इसमें कचरे का विकेंद्रीकरण (गीला और सूखा अलग-अलग) दो गुना करने और हर वॉर्ड में कचरा प्रॉसेस करने सहित कचरे से बिजली उत्पादन शामिल है। बीएमसी घनकचरा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना के बाद लोगों में कचरे को लेकर काफी जागरूकता आई है। लोग पहले के मुकाबले अब कम कचरा इधर-उधर फेंक रहे हैं। इससे कचरा उठाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। मुंबई में कोरोना काल के मुकाबले मेडिकल कचरा काफी कम हो गया है। अब हॉस्पिटल में ही मेडिकल कचरा पैदा हो रहा है।

# सुधीर मुनगंटीवार के आदेश पर नाराज हुई रजा अकादमी

**मुंबईः** महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हुक्म पर रजा अकादमी ने नाराजगी जताई है। अकादमी के अध्यक्ष सईद नूरी ने कहा है कि वह इस बारे में मुस्लिम उलेमाओं और बाकी संबंधित लोगों से मशवरा करेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी मुनगंटीवार को घेरा है। मुनगंटीवार ने रविवार को आदेश जारी किया था कि राज्य में सरकारी कार्यालयों में 'हलो' की बजाए 'वंदे मातरम' बोलें। इस पर रजा अकादमी ने कहा 'हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। वंदे मातरम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दीजिए। ऐसा ऑप्शन दीजिए, जो सबको स्वीकार हो।'

राज्य के पूर्व मंत्री व एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या सब को जेल में डाल दिया जाएगा या पुलिस में मामला दर्ज किया जाएगा? क्या अब आजाद देश में सांस कहां और कैसे लेनी है, यह भी आप से पूछना पड़ेगा? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को राज्य के 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कयिा था।

# जूलर ने अंबानी को क्यों दी धमकी? पुलिस के लिए भी रहस्य...

**मुंबईः** उद्योगपति मुकेश अंबानी को कथित तौर पर गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। डी बी मार्ग पुलिस ने सोमवार को बोरीवली से एक 56 वर्षीय ज्वैलरी डिजाइनर की गिरफ्तारी की है। वहीं इसके बाद पुलिस इस बात की तहकीकात में लगी है कि आखिरकार आरोपी क्यों इस तरह से बार-बार फोन कर धमकी दे रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी को किसी सार्वजनिक पोर्टल से नंबर मिला था। आरोपी का नाम विष्णु विधु भौमिक है, जिसने ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के पास स्थित सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर नौ बार कॉल कर धमकी दी थी। आरोपी ने अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर सुबह 10.39 से दोपहर 12.04 के बीच कॉल की। आरोपी को किसी सार्वजनिक पोर्टल से नंबर मिला था। उसने एक कॉल में स्वर्गीय श्री धीरूभाई अंबानी के नाम का भी जिक्र किया था। मामले की जांच कर रहे पुलिस उपायुक्त नीलोत्पाल ने कहा कि, अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संदिग्ध को बोरीवली (पश्चिम) से हिरासत में लिया और उसे डी बी मार्ग पुलिस थाने ले आई।

# मौत का हाईवे बनता जा रहा है मुंबई- पुणे एक्सप्रेस वे...

## 4 महीने में 5,332 डेथ, 10 हजार से ज्यादा जख्मी

**मुंबईः** पूर्व विधायक विनायक मेटे की मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ट्रैफिक एक्सपर्ट इसके पीछे एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को वजह मानते हैं। हाइवे पर ट्रैफिक की गति के बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़े एक अधिकारी कहते हैं कि एक्सप्रेस वे पर 2016 में प्रति 2 किमी की दूरी में 3 मौतें दर्ज की गई थीं, जो राष्ट्रीय औसत प्रति 2 किमी के दायरे में 1.5 मौतों से 150 फीसदी अधिक हैं। यह आंकड़ा बताता है कि देश में सबसे घातक हादसा एक्सप्रेस वे पर ही होता है। राज्य परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी मिलिंद महैस्कर कहते हैं कि एक्सप्रेस वे पर चार पहिया वाहनों के लिए गति सीमा को 120 किमी प्रति घंटे से घटाकर 100 किमी प्रति घंटे करने से दुर्घटनाओं पर कुछ हद तक अंकुश लगाने में मदद मिली है। बावजूद इसके, आज भी लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं।

हालांकि, ट्रैफिक एक्सपर्ट जगदीप देसाई कहते हैं कि विदेशों की तरह भारत में भी भारी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना चाहिए, जिससे उनको लेन में चलने के लिए ट्रैक किया जा सके। राज्य परिवहन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सप्रेस वे पर होने वाली मौतों में कमी आई है। 2018 में 100 किलोमीटर के दायरे में 110 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2021 में यह संख्या 82 पर सिमट गई।

मुंबई में सड़क हादसे राज्य में होने वाले सड़क हादसों की तुलना में 42 फीसदी अधिक हैं। हाइवे ट्रैफिक रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे राज्य में जनवरी से मई तक घटी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 19,833 है जिनमें से मुंबई में हुए सड़क हादसों की संख्या ही 8,768 है। हालांकि, पूरे राज्य में हुए सड़क हादसे में पिछले 4 महीने में 5,332 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 10 हजार से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं। इसके बावजूद राहत देने वाली बात है कि खराब सड़कें एवं इसकी वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मुंबई में लोग कम मारे जाते हैं। यानी महानगर में घटने वाली दुर्घटनाओं में मरने वालों की अपेक्षा जख्मी होने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। इसके विपरीत अहमदनगर में 554, पुणे में 539, नासिक में 536 और कोल्हापुर में 406 सड़क हादसे जनवरी से मई के बीच दर्ज किए गए हैं।

ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट जगदीश देसाई के मुताबिक अधिकतर भारी वाहनों में लगी लाइट की रोशनी खराब होती है। इसके चलते रात में या मॉनसून के दौरान भारी वाहन चालक कार एवं मोटर चालकों को सही से देख नहीं पाते हैं, जो उनके लिए खतरनाक साबित होता है। वहीं ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट संदीप सोनावणे के मुताबिक जहां कहीं अच्छी सड़कें होती हैं, उनकी वजह से भले ही सड़क हादसे कम होते हैं।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : बुधवार 17 अगस्त 2022

# केंद्र के स्तर पर कोई भ्रष्टाचार नहीं : राज्यपाल कोश्यारी

**मुंबई :** राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पुणे के काउंसिल हाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने जिला परिषद के गठन के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गत आठ साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार के शासन में केंद्र के स्तर पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कोश्यारी ने कहा कि मोदी जनता के समर्थन के बल पर देश से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नागपुर विभागीय आयुक्त कार्यालय में ध्वजारोहण

किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए फडणवीस ने सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण में कहा कि भारत को बलशाली और विकसित देश बनाना है और सभी को साथ लेकर विकास करना है। महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में समाज के सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर विकास की राह पर चलेगी। हम मजबूत महाराष्ट्र की नींव मजबूत महाराष्ट्र से तैयार करेंगे। तिलक भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर पटोले ने कहा कि देश के महानायकों, लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, बलिदान और संघर्ष से देश को आजादी मिली, लेकिन आज तिरंगा को न मानने वाले लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहे और तिरंगा का मान-सम्मान कायम रखें।

# दहिसर से भायंदर का सफर होगा आसान

## - ब्रिज से 45 मिनट का सफर 10 मिनट में होगा पूरा

**मुंबई:** पश्चिम उपनगर में भायंदर से बोरीवली के बीच सबसे बड़ी ट्रैफिक होती है जिसके चलते वाहन चालकों का सिर्फ इस परिसर में बड़ा समय बर्बाद होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मनपा जोर शोर से लगी हुई इसी तरह मुंबई भर वाली ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए मुंबई मनपा ने काई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मनपा प्रशसन ने ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए कोस्टल रोड के साथ दहिसर-भायंदर लिंक रोड बनाने का काम कर रही है। लिंक रोड के बनने से मुंबई से मीरा-भायंदर, वसई-विरार, पालघर, गुजरात जाने में लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना नहीं

करना पड़ेगा। मनपा ने 6 किमी लंबे इस रोड पर ज्यादातर हिस्सा में एलिवेटेड ब्रिज बनाने का निर्णय लिया है । इस पूरी दूरी पर ब्रिज बनाने और रोड बंनाने के लिए मनपा ने 1800 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। इससे प्रोजेक्ट को गति मिलने की उम्मीद बढ़ी है। दहिसर से मीरा-भायंदर के बीच की दूरी तय करने में अभी गाड़ियों को करीब 45 मिनट का समय लगता है। एलिवेटेड ब्रिज बनने से यह दूरी महज 10 मिनट में तय की जा सकेगी। दहिसर से मीरा-भायंदर के बीच ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए दहिसर पश्चिम हिस्से को खाड़ी मार्ग से भायंदर पश्चिम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान को फ्लाईओवर के जरिए जोड़ा जाएगा। इसके लिए मनपा को सॉल्ट पेन विभाग की जगह को अधिग्रहण करना पड़ेगा। जिस पर 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। इसके बाद 120 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा। बीएमसी रोड डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर सतीश थोसर ने बताया कि इस लिंक रोड के बनने से दहिसर- मीरा-भायंदर के बीच दूरी कम होने के साथ ही मुंबई से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा।

# राष्ट्रपति ने नागरिकता बिल लौटाया, अब देउबा सरकार के आगे नई चुनौती

**नेपाल :** नेपाल में बहुचर्चित नागरिकता कानून संशोधन बिल को वापस संसद को लौटा देने के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के कदम से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन के लिए नई समस्या खड़ी हो गई है। राष्ट्रपति भंडारी ने संसद से पारित बिल पर दस्तखत करने के बजाय पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए उसे संसद को लौटा दिया है। संसद से पास होने के बाद इस बिल को प्रतिनिधि सभा के स्पीकर ने पिछले 31 जुलाई को राष्ट्रपति की मुहर के लिए उनके पास भेजा था। संसद में इस बिल का मुख्य विपक्षी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) ने विरोध किया था। राष्ट्रपति के कदम को उसके रुख की पुष्टि की रूप में देखा जा रहा है। शेर बहादुर देउबा की गठबंधन सरकार को उम्मीद थी कि इस बिल के कानून का रूप लेने पर उसे खास कर देश के मधेस इलाके में बड़ा सियासी फायदा मिलेगा। मधेस इलाके की पार्टियां देश में नया संविधान बनने के बाद से नागरिकता कानून में बदलाव की मांग कर रही थीं।

पर्यवेक्षकों के मुताबिक इस बिल पर राष्ट्रपति के दस्तखत में हो रही देर से देश में आशंकाएं पैदा हुई थीं। नेपाल के संविधान के मुताबिक संसद से पारित किसी बिल का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रपति 15 तक दस्तखत टाल सकते हैं। उसके बाद या तो उन्हें दस्तखत करना होगा, या फिर पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाना होगा। राष्ट्रपति भंडारी ने ये अवधि पूरी होने से पहले बिल को वापस संसद को भेज दिया। राष्ट्रपति भवन के सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि राष्ट्रपति ने बिल पर अपनी 15 चिंताएं जताई हैं। उन्होंने संसद से उन चिंताओं पर विचार करने का अनुरोध किया है।

संसदीय सूत्रों ने बताया है कि संविधान के मुताबिक संसद चाहे तो राष्ट्रपति की चिंताओं को ठुकरा सकती है। संसद अब जिस रूप में भी दोबारा विधेयक पास करेगी, उस पर राष्ट्रपति को 15 दिन के अंदर दस्तखत करना होगा। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि ये संवैधानिक प्रावधान है। बिल को लौटा देने से जो राजनीतिक सवाल उठे हैं, अब सत्ता पक्ष को जनता के बीच उन पर जवाब देना होगा।

# बरसाती बीमारियो की चपेट में घिर रही मुंबई...!

**मुंबई :** बरसाती बीमारियो का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जबकि स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या में एक सप्ताह के भीतर दोगुनी हो गई है। इस बीच कोरोना मरीजों की संख्या भी फिर एक बढ़ रही है जिससे मनपा की चिंता बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से बारिश होने का भी कोई समय नहीं हो रहा है। बारिश के असमय हो जाने से लोगो के भीग जाने का प्रमाण बढ़ जा रहा है पिछेल कुछ दिनों से त्योहारों की आई तेजी से भी बड़ी संख्या में लोग घर के बाहर निकल रहे है जिससे बरसाती बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

मलेरिया डेंगू जैसे मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है स्वाइन फ़्लू के मरीजों का प्रमाण भी तेजी से बढ़ रहा है एक सप्ताह के भीतर स्वाइन फ़्लू के मरीजों की सांख्य दो गुनी हो गई है। बता दे कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आए उतार-चढ़ाव को देखते हुए इस बात के संकेत हैं कि सितंबर महीने में चौथी लहर का प्रकोप होगा.मनपा जहां चौथी लहर को समय रहते फैलने से रोकने के उपाय कर रही है, वहीं अब महामारी की बीमारियां सामने आ गई हैं.. 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच स्वाइन फ्लू के 42 मामले सामने आए थे। जबकि 8 से 14 अगस्त के बीच आठ दिनों में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 80 पहुंच गई और कुल मरीजों की संख्या 138 पहुंच गई है. जबकि मलेरिया के 412, डेंगू-73, लेप्टो-29 मरीज मिले हैं।इससे मानसून के दौरान महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपील की गई है कि उचित सावधानी बरती जाए.

# मशीनी झाड़ू से सड़को की सफाई पर मनपा का जोर

**मुंबई :** सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई के लिए मनपा अब मशीनी झाड़ू पर जोर दिया है। मनपा प्रशासन अब 35 मशीनी झाड़ू खरीदने का निर्णय लिया है। मनपा प्रशासन कचरे की समस्या को दूर करने के लिए मुंबई में 9 स्थानों पर 2 मैट्रिक टन का बायोमिथेन लगाने का भी निर्णय लिया है जिसकी निविदा प्रक्रिया मनपा ने शुरू की है। मनपा प्रशासन ने मुंबई शहर को स्वच्छ बनाने के लिए खासकर मुंबई की मुख्य सड़को को अच्छी और जल्द साफ सफाई हों इसके लिए मशीनी झाड़ू की संख्या बढ़ाने का निर्णय मनपा ने लिया है।मनपा अभी तक मुंबई की कुछ ही सड़को पर मशीनी झाड़ू का उपयोग कर रही है।मनपा अब 35 और मशीनी झाड़ू लेने का निर्णय लिया है ।मशीनी झाड़ू से सड़को की साफ सफाई कम समय अच्छी तरीके से हों जाती है । सफाई के लिए मनुष्य बल का उपयोग भी कम होता है। अभी तक सिर्फ

चौपाटी और पर्यटन स्थल सहित शहर परिसर की कुछ प्रमुख सड़को की सफाई के लिए ही मशीनी झाड़ू का उपयोग होता था अब सभी मुख्य सड़को की सफाई मशीनी झाड़ू से की जा सकेगी।मनपा का मानना है कि इससे खर्च में कटौती होगी और अच्छी सफाई के साथ साथ समय की भी बचत होगी। मनपा प्रशासन के सामने कचरा बड़ी समस्या बन गई है।डंपिंग ग्राउंड की खत्म होती क्षमता और रोजाना मुंबई में बढ़ते कचरे का प्रमाण मनपा के लिए सिरदर्द हो गया है। इसके लिए मनपा ने कचरे की समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 2030 तक का नया विजन तैयार किया है जिसके अनुसार कचरे को कम से कम डंपिंग ग्राउंड पर ले जाना है।

# मुंबई में डेटिंग एप पर पहले महिला से की दोस्ती, फिर शादी का वादा कर साइबर अपराधी ने ठग लिए 8 लाख

**मुंबई :** मुंबई में साइबर अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आलम ये है कि साइबर क्रिमिनल्स अब डेटिंग एप पर भी सक्रिय है और भोली-भाली महिलाओं को बेवकूफ बनाकर उनसे ठगी कर रहे हैं. ताजा मामले में अंधेरी (पूर्व) की एक 49 वर्षीय महिला से एक साइबर ठग ने शादी का वादा कर 10,350 अमेरिकी डॉलर (करीब 8.28 लाख रुपये) ठग लिए.

**शिकायतकर्ता की अप्रैल में एक डेटिंग ऐप पर हुई थी आरोपी से दोस्ती**

बता दें कि शिकायतकर्ता की अप्रैल में एक डेटिंग ऐप पर अमेरिकी नागरिक होने और तुर्की के एयरबेस अस्पताल में कार्यरत होने का दावा करने वाले एक

धोखेबाज से दोस्ती हुए थी. साइबर क्रिमिनल ने इस दौरान महिला को झांसे में ले लिया और उससे शादी करने का वादा करने के बाद उसका विश्वास हासिल कर लिया. महिला की शिकायतकर्ता के अनुसार, स धोखेबाज ने अपना परिचय पैट्रिक एंडरसन आमिर के रूप में दिया था, उसने पहले यह दावा किया था कि उसने 500 अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर किए है लेकिन उसका अपना एटीएम कार्ड खो गया है. शिकायतकर्ता ने बताया कि, '' इसके बाद आरोपी ने उससे शादी करने के लिए मुंबई आने के लिए दस्तावेजों की जांच, वीजा प्रोसेसिंग, हवाई किराए और अन्य औपचारिकताओं के लिए पैसे ट्रांसफर करवा लिए'' महिला ने 7 अगस्त को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार किया लेकिन वह नहीं आया. फिर एक दिन बाद आमिर का दोस्त होने का दावा करने वाल जेफ्रिन नाम के शख्स ने 9 अगस्त को उसे बताया कि आमिर मुंबई की यात्रा नहीं कर सकता है क्योंकि वह अस्पताल में भर्ती है और उसके पास वैध वीजा या यात्रा टिकट भी नहीं है.

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : बुधवार 17 अगस्त 2022

# मुंबई में 100 साल पुरानी जर्जर इमारत को ढहाने की इजाजत, लोगों को भवन छोड़ने के निर्देश

**मुंबई :** बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को दक्षिण मुंबई में एक सदी पुरानी जर्जर इमारत को गिराने की मंजूरी दे दी है और इसके रहने वालों को परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को पारित एक आदेश में कहा कि भवन 'एच एन पेटिट विडोज होम' एक व्यस्त सड़क पर स्थित है और कोई भी अप्रिय घटना होने पर इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने बीएमसी तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि इमारत जर्जर और खतरनाक स्थिति में है और इसलिए इसे गिराया जाना चाहिए।

समिति की रिपोर्ट के आधार पर बीएमसी ने इस साल अप्रैल में भवन के

मकान मालिक को परिसर खाली करने के लिए पत्र जारी किया था। इमारत के कुछ रहने वालों और इसके भूतल पर दुकानें चलाने वाले किरायेदारों ने हालांकि, परिसर को खाली करने से इनकार कर दिया और अदालत का रुख करेत हुए कहा कि भवन को केवल मामूली मरम्मत की जरूरत है। पांच मंजिला इमारत 100 साल से अधिक पुरानी है। इसका उपयोग विधवाओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। भवन की खराब स्थिति के कारण यहां रहने वाली विधवाओं को 2019 में दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया। अक्टूबर 2021 में बीएमसी ने संरचनात्मक ऑडिट बैठक की, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि इमारत जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है और गिर सकती है। इससे न सिर्फ रहवासियों बल्कि राहगीरों की जान को भी खतरा है। उन्होंने कहा कि इमारत को जल्द से जल्द गिराया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि यह इमारत भुलेश्वर (दक्षिण मुंबई में) के बहुत भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है और बहुत से लोग उस सड़क से गुजरते हैं।

# विपक्ष ने किया चाय समारोह का बहिष्कार...!

## अजित पवार ने बताई वजह

**मुंबई :** महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा. विपक्षी दलों ने अधिवेशन की पूर्व संध्या पर चाय समारोह का बहिष्कार किया है। इस मौके पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अजित पवार ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए एकनाथ शिंदे सरकार की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने यह भी बताया कि अधिवेशन में किन मुद्दों को उठाया जाएगा। जिस तरह से सरकार सत्ता में आई वह अभी कानूनी नहीं है। शिंदे सरकार का गठन लोकतांत्रिक और संसदीय परंपरा के चीथड़ों को फेंक कर किया गया है। इस सरकार का भविष्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. कन्वेंशन कम अवधि का है। हमने दस दिनों के लिए सत्र आयोजित करने की मांग की थी। लेकिन अजीत पवार ने कहा कि उन्हें इस बारे में सोचने के लिए कहा गया था। कुल मिलाकर भारी बारिश हुई है। वैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई है और भंडारा और गोंदिया के बीच यातायात बाधित हो गया है। किसानों को उस तरह से मदद नहीं मिली, जैसी होनी चाहिए थी। हम इन मुद्दों को सम्मेलन में उठाएंगे। भारी बारिश के शिकार लोगों की मांगें हैं। गीला सूखा घोषित, अजित पवार ने 75 हेक्टेयर व बागबानी के लिए 1.5 लाख रुपये की मदद की मांग की अजीत पवार ने भारी बारिश वाले इलाकों में छात्रों की पढ़ाई की फीस माफ करने की मांग की. सरकार कोई भी हो, जब सरकार संकट में होती है, तो पर्याप्त मदद की जरूरत होती है। लेकिन यह सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। फसल ऋण वितरण अगस्त में लक्ष्य के आधे तक ही पहुंच पाया है। जो एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन तुच्छ विषयों पर अधिक चर्चा की जाती है।अब वंदे मातरम को बीच में ले लिया गया। इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन अजीत पवार ने कहा कि महंगाई को लेकर क्या फैसला होगा, जीएसटी में कटौती को लेकर क्या रुख होगा, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को थोड़ा कम किया गया है.

# एनएसई फोन टैपिंग मामला : मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त की जमानत अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी

**नयी दिल्ली :** दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग और जासूसी से जुड़े धन शोधन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का रुख जानना चाहा। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने पांडे की जमानत अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए उसे स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने पांडे और उनकी कंपनी आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर उससे भी जवाब मांगा। इन याचिकाओं में कथित फोन टैपिंग के संबंध में एजेंसी द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है। सीबीआई के मुताबिक, आईसेक ने अन्य आरोपियों के साथ साजिश रचते हुए 2009 से 2017 के बीच एनएसई में एमटीएनएल लाइनों को अवैध रूप से इंटरसेप्ट (फोन कॉल पर गुप्त रूप से नजर रखना) किया और विभिन्न एनएसई अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड किए। जांच एजेंसी का आरोप है कि आईसेक द्वारा सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति के बिना टेलीफोन की निगरानी की गई थी, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है। यही नहीं, सीबीआई का यह भी आरोप है कि एनएसई कर्मचारियों को उनके फोन कॉल रिकॉर्ड करने की न तो जानकारी दी गई थी, न ही इस बाबत उनकी सहमति ली गई थी। ईडी ने पांडे को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जमानत अर्जी खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाले पांडे की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने उच्च न्यायालय से याचिका पर जल्द सुनवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा, ''पांडे एक वरिष्ठ नागरिक हैं। वह पुलिस आयुक्त रह चुके हैं। वह भागने वाले नहीं हैं।'' पांडे की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि सीबीआई की प्राथमिकी को इस आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ ऐसा कोई अपराध नहीं बनता है, जैसा कि जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है।

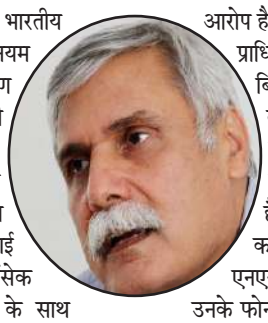

# बीजेपी एमएलसी के सहयोगी का फेसबुक अकाउंट हैक

## भाजपा नेताओं के लिए लिखी गई गालियां... !

**दादर :** बीजेपी से विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य राजहंस सिंह के एक निजी सहायक ने शिकायत दर्ज कराई है कि पार्टी की नई मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार के सोशल मीडिया पेज पर अपमानजनक और अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने के लिए उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया था. दिनेश दहीवलकर, 14 अगस्त को कुरार थाने में शिकायत लेकर पहुंचे थे. दहीवलकर ने कहा कि आशीष शेलार को भाजपा का मुंबई प्रमुख बनाए जाने के बाद, पार्टी कार्यकर्ताओं ने रविवार शाम दादर में एक समारोह आयोजित किया था, जिसमें सिंह सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे. शेलार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी लोगों को इस घटनाक्रम की जानकारी दी थी.

**शेलार की पोस्ट के कमेंट बॉक्स में की गई टिप्पणी**

दहीवलकर ने आरोप लगाया कि किसी ने उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया और शेलार की पोस्ट के नीचे भाजपा नेताओं के खिलाफ अपमानजनक और अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की. इसके तुरंत बाद,

सिंह ने दहीवलकर को फोन किया और कथित पोस्ट के बारे में पूछताछ की. बकौल द इंडियन एक्सप्रेस, दहीवलकर ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने उनका अकाउंट हैक कर लिया और शिकायत के साथ पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पहचान की चोरी और मानहानि के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई.

**हाल ही में मुंबई बीजेपी के प्रमुख बने हैं शेलार**

बता दें कि जिस नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पांच साल पहले शहर के निकाय चुनावों में सबसे अधिक संख्या में जीत हासिल की, उन्हीं आशीष शेलार को फिर से अपनी मुंबई इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. पुनर्गठन में चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य इकाई में कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल की जगह ली है. हाल ही में मंत्री बनाए गए मंगल प्रभात लोढ़ा ने शेलार के लिए रास्ता बनाया. बांद्रा पश्चिम के विधायक शेलार, देवेंद्र फडणवीस सरकार में केवल कुछ महीनों के लिए स्कूली शिक्षा मंत्री थे, इससे पहले उन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों और 2014 के विधानसभा चुनावों में मुंबई में भाजपा को शानदार सफलता दिलाई. बीच में 2017 के बीएमसी चुनाव आए, जिसमें भाजपा ने शिवसेना को लगभग पछाड़ दिया, जिसमें बीजेपी की शिससेना से सिर्फ दो सीटें कम थी.

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैजल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नंबर 3-4, अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट, सोनावाला क्रॉस रोड नंबर 12, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई - 63 से छपवाकर रूम नंबर 15 रमजान बिन 17- सी, वंजावडी, माहिम (वेस्ट), मुंबई - 400016 से प्रकाशित किया . संपर्क कार्यालय 1 ए, ग्राउंड फ्लोर, साहिल मेन्शन, बालमिया लेन, माहिम (वेस्ट), मुंबई - 400016.
मोबाइल नंबर 9987775650 व्हाट्सएप नंबर 9987775650 ईमेल- editor@rokthoklekhaninews.com -किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मुंबई होगा!